भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-5473
दिनांक 03 अप्रैल, 2025 को उत्तरार्थ

उत्तराखंड में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना

5473. श्री अजय भट्ट:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने उत्तराखंड में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के कार्य-निष्पादन का कोई मूल्यांकन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य में कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया है और कितने गांवों का विद्युतीकरण किया जाना है;

(घ) क्या सरकार द्वारा शेष गांवों के विद्युतीकरण के लिए कोई विशेष कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (ग) : भारत सरकार (जीओआई) ने वर्ष 2014 में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) शुरू की थी। राज्यों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, देश के सभी आबाद गैर-विद्युतीकृत जनगणना गांवों को दिनांक 28 अप्रैल, 2018 तक विद्युतीकृत कर दिया गया। डीडीयूजीजेवाई के तहत उत्तराखंड राज्य के 91 गांवों सहित राष्ट्रीय स्तर पर कुल 18,374 गांवों को विद्युतीकृत किया गया। इसके अलावा, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सभी इच्छुक घरों और शहरी क्षेत्रों में सभी इच्छुक गरीब घरों को विद्युतीकृत किया गया, जिनमें से उत्तराखंड राज्य में 2,48,751 घरों को विद्युतीकृत किया गया।

डीडीयूजीजेवाई का प्रभाव आकलन अध्ययन मेसर्स अर्न्स्ट एंड यंग एलएलपी द्वारा वर्ष 2022 में अखिल भारतीय स्तर पर किया गया था, जिसमें बताया गया था कि अध्ययन के अंतर्गत शामिल 100% गांवों और उपभोक्ताओं ने विद्युत आपूर्ति के घंटों में सुधार की सूचना दी है। अध्ययन में उल्लेख किया गया है कि कई डिस्कॉम ने नए अवसंरचना के कारण वितरण हानियों को कम किया है। बिलिंग दक्षता और एसीएस-एआरआर

अंतर में सुधार, डिस्कॉम के प्रचालन और वित्तीय प्रदर्शन के महत्वपूर्ण संकेतक, ने भी डीडीयूजीजेवाई के बाद सुधार दिखाई दिया है। तथापि, यह उल्लेख करना उचित है कि, जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया है, डीडीयूजीजेवाई के कार्यान्वयन के दौरान, डिस्कॉम ने अन्य स्कीमों के तहत आपूर्ति क्षेत्रों में विकास कार्य किए, जिसका विभिन्न मापदंडों में सुधार में योगदान हो सकता है।

इसके अलावा, अध्ययन में इस स्कीम के व्यवसाय विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, सामुदायिक सुरक्षा और बैंकिंग पर महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव पर भी प्रकाश डाला गया।

अध्ययन में उत्तराखंड राज्य के संबंध में निम्नलिखित उल्लेख किया गया है:

i. वर्ष 2015 में 18 घंटे की तुलना में वर्ष 2022 में विद्युत आपूर्ति के घंटे बढ़कर 23 घंटे हो गए।
ii. वर्ष 2015 और 2022 के बीच आय में 33% की वृद्धि देखी गई।

(घ) और (ङ) : भारत सरकार (जीओआई) ने वित्तीय रूप से स्थिर और प्रचालन रूप से दक्ष वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार लाने के उद्देश्य से जुलाई, 2021 में संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) शुरू की।

सौभाग्य के दौरान छूटे हुए घरों के लिए आरडीएसएस के तहत**,** जहाँ भी व्यवहार्य पाया गया**,** ग्रिड आधारित विद्युतीकरण कार्यों को भी संस्वीकृत किया गया है। अब तक, 10,19,030 घरों के ग्रिड विद्युतीकरण के लिए 4,643 करोड़ रुपये की राशि के कार्यों को संस्वीकृत किया गया है। उत्तराखंड राज्य के लिए, 2049 घरों के विद्युतीकरण कार्य के लिए 14.59 करोड़ रुपये की लागत की परियोजनाओं को संस्वीकृत किया गया है।

****